

योजना (पी0 आई0) एफ (11) 3/2018-19
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक:

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश शिमला-171002

प्रेषित:

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला-171002/16⁴¹ जनवरी, 2019

विषय:- वर्ष 2018-19 के प्रक्रियाधीन बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 07/01/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

महोदया/महोदय,

आपको वर्ष 2018-19 के प्रक्रियाधीन बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2019 को प्रातः 10:30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही संलग्न की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिये गए निर्णयानुसार अपने विभाग से सम्बन्धित वर्ष 2018-19 के प्रक्रियाधीन बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन की नवीनतम प्रगति सूचना योजना विभाग को प्रशासनिक सचिव के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कृपा करें। यह पत्र और उपरोक्त बैठक की कार्यवाही योजना विभाग की वेबसाईट: hpplanning.nic.in पर भी उपलब्ध है।

बैठक की कार्यवाही मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदनोपरान्त जारी की जा रही है।


भवदीय,

रविन्द्र कुमार
(रविन्द्र कुमार)
उप-निदेशक(योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
दूरभाष: 2620656

पृ०संख्या: योजना(पी०आई०)एफ(११)३/२०१८-१९ दिनांक शिमला-२१६^५ जनवरी, २०१९

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

१. निजी सचिव, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-१७१००२.
२. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-१७१००२.


उप-निदेशक(योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-१७१००२
दूरभाष: २६२०६५६

वर्ष 2018-19 के प्रक्रियाधीन बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 07/01/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुबन्ध-क पर सलग्न है।

अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) ने बैठक का संचालन करते हुए सूचित किया कि वर्ष 2018-19 के बजट आश्वासनों में कुल 125 मुख्य पैरे और 249 सब पैरे थे जिसमें से 71 मुख्य पैरे तथा 162 सब पैरे कार्यान्वित हो चुके हैं। 54 मुख्य पैरे तथा 87 सब-पैरे प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय की समस्त विभागीय सचिवों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रियाधीन बजट आश्वासन कार्यान्वयन स्तर पर पाए गए:-

1. पैरा सं०-14, 55, 57 (ग्रामीण विकास)

पैरा सं०:-14 (3) हर जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में जन मंच का सफल आयोजन किया जा रहा है।

पैरा सं०:-55 (2) मनरेगा में बेहतर पानी निकासी के लिए सड़क के साथ नालियों व मकानों के साथ छोटे पिट का निर्माण हेतु सभी कार्यान्वयन संस्थाओं को निर्देश दे दिये गए हैं।

पैरा सं०:-57 स्वयं सहायता समूहों को और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके **Revolving Fund** को 40,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

2. पैरा सं०:-16, 107, 110, 111, 113 (लोक निर्माण)

पैरा सं०:-16 शीघ्र ही दोनों विभागों में **WMIS** लागू कर दिया जाएगा।

पैरा सं०:-107 58 **DPRs** हेतु **Consultant** नियुक्त किये जा चुके हैं।

पैरा सं०:-110 (1) सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली का प्रावधान कर दिया गया है। (2) मुख्यमन्त्री कार्यालय के अधीन एक स्वतन्त्र गुणवत्ता परीक्षण स्क्वैड (**Independent Quality Check Squad**) का गठन कर दिया गया है। (3) सड़कों की टारिंग का लक्ष्य 1785 किलोमीटर से बढ़ाकर 2,500 किलोमीटर किया गया है। (5) **OPBMC (Output and Performance Based Maintenance contract)** नामक पायलट परियोजना के अन्तर्गत 350 किलोमीटर के अतिरिक्त मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

पैरा सं०:-111 रोहतांग दर्रे को सर्दियों में भी खुला रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं को आमन्त्रित किया जाना शेष है।

पैरा सं०:-113 (1) तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रमुख पुलों की सुरक्षा का लेखा परीक्षण के लिये चयन प्रक्रिया चालू है। (2) **मुख्यमन्त्री सड़क योजना** के अन्तर्गत गाँवों/बस्तियों को शीघ्रता से सड़क से जोड़ने के लिये विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

3. पैरा सं०:-75, 76, (राजस्व)

पैरा सं०:-75 (1) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए **"National Generic Document Registration System"** प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर दी जाएगी। (2) "सरकारी भूमि" मॉड्यूल को शुरू कर दिया जाएगा।

पैरा सं०:-76 सूखे की स्थिति में प्रदेश आपदा प्रबन्धन निधि से पेयजल, चारा तथा किसानों के लिए खरीद उपदान प्रदान किया जा रहा है।

4. पैरा सं०- 18, 19 (सूचना प्रौद्योगिकी)

पैरा सं०-18 (1) सभी ग्राम पंचायतों को, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारत नेट फेज-2 के अन्तर्गत तीव्र गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

पैरा सं०-19 (1) सभी विभागों द्वारा 5 लाख से ज्यादा सरकारी खरीद प्रक्रिया की निविदाओं को **e-procurement Portal** के माध्यम से जारी करना एवं

Government e-Market (GeM) पर उपलब्ध वस्तुएं वहीं से क्रय की जा रही है। (2) काँगड़ा जिले में आई0टी0 पार्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5. पैरा सं0- 25, 37 (उद्यान)

पैरा सं0-25 (1) 2600 सेब के बगीचों में कौलोनल रूट स्टॉक पर उच्च पैदावार किस्मों का कल्मीकरण बारे अवगत करवाया गया कि वर्ष 2018-19 में 2000 बगीचों हेतु पौधों का वितरण किया गया है। (2) उष्ण कटिबंधीय फल जैसे आम, लीची, अमरुद एवं नींबू प्रजाति के फलों के बगीचों को 400 हैक्टेयर में समूह के आधार पर लगाए जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि वर्ष 2018-19 में 32 है0 क्षेत्रफल में पौधों की उपलब्धता एवं मांग के अनुसार बागीचे लगाए गए हैं। (7) सभी समूहों में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। (8) CA शीतभण्डारण केन्द्र, ग्रेडिंग तथा पैकिंग घरों के निर्माण तथा मार्केट यार्डों के विकास हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।

पैरा सं0-37 (1) CA शीतभण्डारण केन्द्र, ग्रेडिंग तथा पैकिंग घरों के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। (3,4,5,6) भारत सरकार की "प्रधानमंत्री कृषि सम्पदा योजना" के अन्तर्गत एकीकृत शीत भण्डारण, खाद्यान्न प्रसंस्करण (Processing) तथा संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने, कृषि प्रसंस्करण (Processing) समूह की अधोसंरचना के विकास, भारत सरकार से इस योजना में सहायता लेने वाली विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमन्त्रित करने तथा खाद्यान्न विधायन से जुड़े उद्योगों को Potato Chips का उद्योग काँगड़ा व कुल्लू जिले में स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

6. पैरा सं0- 27, 50 (कृषि)

पैरा सं0-27 वर्ष 2018-19 में 30 करोड़ के प्रावधान सहित नई "सौर सिंचाई योजना" को प्रारम्भ कर दिया गया है।

पैरा सं0-50 उपदान वाली समान योजनाओं में सहायता ढांचे तथा आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु कृषि एवं उद्यान विभागों की संयुक्त समिति का गठन कर दिया गया है।

7. पैरा सं0- 51 (मत्स्यपालन)

पैरा सं0-51 (1,2) 100 ट्राउट रेसवेज में 5 लाख ट्राउट बीज का भण्डारण तथा प्रदेश में 11 नई ट्राउट हैचरियों तथा 100 ट्राउट इकाईयों की स्थापना कर दी गई है। (3) मछुआरों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करवाने के लिये समुचित मत्स्य संस्थान कोचि का सहयोग प्राप्त करके आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। (4) मछुआरों को उचित दाम पर Fish Feed की उपलब्धता हेतु Fish Feed इकाई की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु भूमि क्रय हेतु स्टैम्प ड्यूटी 3 प्रतिशत तथा यन्त्र एवं मशीनों पर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है।

8. पैरा सं0- 52 (पशुपालन)

पैरा सं0-52 (1) हिमाचल प्रदेश में "गौ-सेवा आयोग" का गठन कर दिया गया है।

9. पैरा सं0- 63 (वन)

पैरा सं0-63 (1,2) राज्य CAMPA की निधि से अगले 3 वर्षों में 22 वन विहार/इको पार्क की स्थापना तथा प्रदेश में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 25 नए इको पर्यटन स्थान आवंटित करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

10. पैरा सं0- 77 (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य)

पैरा सं0-77 (1,2) चयनित शहरों में पायलट आधार पर 24X7 जल की उपलब्धता तथा चालू 3,448 पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए, चरणबद्ध रूप से ऑटोमेशन प्रक्रिया प्रगति पर है।

11. पैरा सं0- 80, 81, 84, 85, 97 (उद्योग/ लोक निर्माण)

पैरा सं0-80 (1) पट्टे पर भूमि नियमों के सरलीकरण एवं मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है। (3)

अन्नापत्ति प्रमाणपत्रों की आवश्यकताओं को कम करने तथा तय समय सीमा में न दिए जाने की स्थिति में डीम्ड अनुमति मानने का प्रावधान कर दिया गया है।

पैरा सं०-81 प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु नीति निर्धारित की गई है।

पैरा सं०-84 (3) बरोटीवाला-मंधाला-परवाणु तथा बरोटीवाला गुनाई परवाणु सड़क को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है।

पैरा सं०-85 सभी खनन स्थानों को ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं द्वारा आबंटित किया जा रहा है।

पैरा सं०-97 प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यम विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

12. **पैरा सं०- 92 (पर्यटन)**

पैरा सं०-92 (3) उड़ान-2 योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त हेलीपैडों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

13. **पैरा सं०- 98, 99, 102 (श्रम एवं रोजगार/ कौशल विकास)**

पैरा सं०-98 (2,3) एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत रोजगार सम्बन्धी कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

पैरा सं०-99 (3) उद्योगों में रोजगार प्राप्त युवाओं को 2 वर्ष तक कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है।

पैरा सं०-102 (1) सभी रोजगार केन्द्रों का कौशल पहचान केन्द्र तथा आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है।

14. **पैरा सं०- 100, 141 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)**

पैरा सं०-100 (1) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एकल महिला, विधवा एवं परित्यक्त नारियों को रोजगार दिलाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के उन विद्यार्थियों को, जिन की पारिवारिक आय ₹3 लाख वार्षिक से कम है, को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण एवं निशुल्क कोचिंग के लिये मेधा प्रोत्साहन योजना में प्रावधान कर दिया गया है। (3) दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण अवसरों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर दी गई है।

पैरा सं०-141 (1) नई व्यापक सशक्त महिला योजना एवं सशक्त स्त्री केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है।

15. **पैरा सं०- 105 (परिवहन)**

पैरा सं०-105 (3) चुने हुए नम्बरों के लिए एक निश्चित राशि तय कर e-Auction/Bidding की सुविधा प्रदान की जा रही है।

16. **पैरा सं०- 115 (शहरी विकास/स्वास्थ्य)**

पैरा सं०-115 (1,2,3,4) अधोसंरचना के निर्माण व सेवाओं हेतु Public Private Partnership (PPP) आधारित कार्यों के लिये आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

17. **पैरा सं०- 117 (आबकारी एवं कराधान)**

पैरा सं०-117 (1) शराब की बिक्री हेतु पुरानी थोक बिक्री व्यवस्था बहाल कर दी गई है।

18. **पैरा सं०- 119, 120, 122, 125 (शिक्षा)**

पैरा सं०-119 (1) 2137 सरकारी उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में Multimedia Teaching Aids दो चरणों में उपयोग किये जाएंगे। (2) स्कूलों में पढ़ाने/बोलचाल के कौशल को बढ़ाने के लिए 36 भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना करने हेतु आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है।

पैरा सं०-120 नई योजना मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र के तहत प्रथम चरण में 10 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

पैरा सं०-122 अटल वर्दी योजना के अन्तर्गत पहली, तीसरी, छठी तथा नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक स्कूल बैग का प्रावधान किया जा रहा है।

पैरा सं०-125 नई मेधा प्रोत्साहन योजना आरम्भ कर दी गई है।

19. पैरा सं०- 128 (भाषा, कला एवं संस्कृति)

पैरा सं०-128 (6) वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कवियों/लेखकों/ साहित्यकारों को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्तों में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है।

20. पैरा सं०- 154 (कार्मिक/ वित्त)

पैरा सं०-154 (10) सभी सरकारी विभागों के कार्यमूलक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

प्रक्रियाधीन बजट आश्वासन

1. पैरा सं०-14(समस्त विभाग/ अर्थ एवं संख्या)

पैरा सं०-14 (1) राज्य के सभी अधिनियमों, नियमों तथा योजनाओं को उनके प्रभावों, प्रासंगिकता तथा सरलीकरण की कसौटी पर समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सभी विभाग इस संदर्भ में जो भी संभव हो, अपने अपने मा० मन्त्री के माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री को अवगत करवाएंगे तथा सूचना योजना विभाग को प्रेषित करेंगे।

(2) ऑन लाईन डाटा एकत्रित करने की प्रणाली विकसित करना:- इस मद पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस प्रणाली को विकसित करने के लिये प्रशासनिक स्तर पर बैठक करने से पूर्व इस संदर्भ में संक्षिप्त टिप्पणी सभी प्रशासनिक सचिवों को भेज दी जाए।

2. पैरा सं०-110 (लोक निर्माण)

पैरा सं०-110 (4) सड़कों के रख-रखाव के लिए एक अलग निधि बनाने का प्रस्ताव:- इस संदर्भ में सूचित किया गया कि अभी तक योजना का प्रारूप तैयार किया जाना है।

3. पैरा सं०-17 (राजस्व)

पैरा सं०-17 नई "ई-स्टैम्पिंग" योजना का प्रारम्भ:- प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही राज्य कैबिनेट के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. पैरा सं०-18 (सूचना प्रौ०)

पैरा सं०-18 (2) कागज रहित कार्यालय वातावरण के अन्तर्गत 5 अतिरिक्त विभागों में ई-ऑफिस लागू करना:- इस संदर्भ में सूचित किया गया कि कोष एवं लेखा विभाग को कागज मुक्त कर दिया गया है तथा 20 नए विभागों को कागज मुक्त करने का कार्य प्रगति पर है।

5. पैरा सं०-24 (खाद्य एवं आपूर्ति)

पैरा सं०-24 (1) हिमाचल प्रदेश Hoarding & Prevention Order के अन्तर्गत मूल्य तथा लाभ प्रतिशत निर्धारित करने के प्रावधानों को समाप्त करना।

(2) अन्य नियन्त्रण आदेशों को अभी abeyance में रखा जाना, केवल खाद्यान्नों की कमी होने पर ही इन्हें पुनः लागू करना।

उपरोक्त मदों के संदर्भ में सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इस मद का कार्यान्वयन करना संभव नहीं है।

6. पैरा सं०-38, 42 (कृषि)

पैरा सं०-38 JICA फसल विविधिकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों को शामिल करना:- DPR तैयार करके भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है।

पैरा सं०-42 (1) विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत राज्य में नई मण्डियों का उन्नयन। (3) Himachal Pradesh Agriculture Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation Bill) 2018 का प्रस्ताव।

उपरोक्त मदें अभी प्रक्रियाधीन है।

7. **पैरा सं०-52 (पशुपालन/ ग्रामीण विकास)**
 पैरा सं०-52 (3) गोमूत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत निवेश अनुदान:- यह मद प्रक्रियाधीन है तथा सूचित किया कि निवेश अनुदान हेतु मामला उद्योग विभाग को भेजा जाएगा।
 पैरा सं०-53 (4) गाँव की सार्वजनिक चरागाहों की पहचान तथा उनका प्रबन्धन:- सभी उपायुक्तों को इस संदर्भ में लिखा गया है।
 (5) गौसदन स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि ₹1 पट्टे पर देना:- यह मद प्रक्रियाधीन है।
 (6) बेसहारा पशुओं को महिला मण्डलों द्वारा देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा समुचित उपदान का प्रावधान:- यह मद ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है तथा प्रक्रियाधीन है।
 (7) प्रत्येक विकास खण्ड की एक सर्वोत्तम पंचायत, जहां शत-प्रतिशत पशु पंजीकृत हैं व उन पर टैगिंग कायम है, तथा जहां पशु मालिक, पशुओं को नहीं त्यागते हैं, को विकास कार्यों के लिए ₹10 लाख का पुरस्कार प्रदान करना:- यह मद ग्रामीण विकास तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है तथा प्रक्रियाधीन है।
8. **पैरा सं०-55 (ग्रामीण विकास)**
 पैरा सं०-55 (1) ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धन:- यह मद प्रक्रियाधीन है।
 (3) कचरा एकत्रीकरण हेतु पिकअप वाहन खरीद पर उपदान:- यह मद व्यवहारिक नहीं है तथा इसका कार्यान्वयन संभव नहीं है।
9. **पैरा सं०-80 (उद्योग)**
 पैरा सं०-80 (2) वन संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम में अनुमतियाँ
 (1) प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने तथा अनुमतियों की नियमित परीक्षा करना:- यह मद प्रक्रियाधीन है।
 (2) भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 5 हैक्टेयर तक की शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation) का मामला:- बैठक में इस मद को Drop करने का निर्णय लिया गया।
10. **पैरा सं०-94 (पर्यटन)**
 पैरा सं०-94 (3) तत्तापानी में जल-क्रीडा, स्थान के सौन्दर्यकरण, घाट बनाने के कार्य एवं गर्म पानी के स्रोतों को विकसित करना:- यह प्रक्रियाधीन है।
11. **पैरा सं०-146 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)**
 पैरा सं०-146 प्रदेश के कुछ स्थानों पर "वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र" का प्रावधान:- इस मद पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
12. **पैरा सं०-104, 106 (परिवहन)**
 पैरा सं०-104 (3) हिमाचल पथ परिवहन निगम, बसों में "स्वाईप/टैप मशीन" का प्रावधान। (4) पास धारकों/छूट प्राप्त श्रेणियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा। (5) सभी बस अड्डों पर तथा चुने हुए बस स्टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड का प्रावधान।
 पैरा सं०-106 (1) सड़क परिवहन में रोजगार के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए 1500 नए बस परमिट।
 उपरोक्त सभी मदें प्रक्रियाधीन है तथा निविदाएं आमन्त्रित की गई है।
13. **पैरा सं०-116, 117 (आबकारी एवं कराधान)**
 पैरा सं०-116 डीलरों के हित के लिए "The Himachal Pradesh Settlement of Pending Assessment Cases Bill" 2018 को ला कर डीलरों के हित की सुविधा:- यह मद प्रक्रियाधीन है।

पैरा सं०-117 (2) आबकारी कार्यों पर प्रभावी निगरानी के लिए उत्पादन से खपत तक पूरी श्रृंखला हेतु एक कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रावधान:- इस सम्बन्ध में निविदाएँ आमन्त्रित की जा चुकी हैं।

14. पैरा सं०-119 (शिक्षा)

पैरा सं०-119 (5) SCERT की सहायता से योग पाठ्यक्रम तैयार करना:- पाठ्यक्रम तैयार करके शिक्षा बोर्ड को भेज दिया गया है।

(7) शिक्षकों के स्थानान्तरण तथा पदभार सम्भालने हेतु एक ठोस तथा पारदर्शी स्थानान्तरण नीति का प्रावधान:- यह मद प्रक्रियाधीन है।

15. पैरा सं०-128 (भाषा, कला एवं संस्कृति)

पैरा सं०-128 (5) जिला मुख्यालयों में इन्डोर सभागृहों जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, का निर्माण:- यह मद प्रक्रियाधीन है।

16. पैरा सं०-137 (स्वास्थ्य)

पैरा सं०-137 (3) प्रदेश के दूर-दराज के 50 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को टेलीमैडीसन के अन्तर्गत लाना:- यह मद प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही निविदाएँ आमन्त्रित की जाएगी।

17. पैरा सं०-140 (आयुर्वेद)

पैरा सं०-140 (1) आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी-बूटियों के विपणन के लिए किसानों का देश की प्रमुख फार्मसियों के मध्य सम्पर्क स्थापित करवाना:- यह मद प्रक्रियाधीन है तथा सूचना अपेक्षित है।

18. पैरा सं०-151 (गृह)

पैरा सं०-151 (1) अपराधियों के डाटा हेतु स्वचलित Finger Print Identification प्रणाली व लाइव स्कैनर का क्रय:- यह मद प्रक्रियाधीन है।

19. पैरा सं०-152 (कोष एवं लेखा)

पैरा सं०-152 (1) सरकारी कार्यालयों के बिजली, पानी और टैलीफोन के बिलों के सीधे भुगतान को ई-बिल प्रणाली से जोड़ना। (2) ई-सेलरी में कर्मचारियों का आधार नम्बर दर्ज करना।

उपरोक्त दानों मदें प्रक्रियाधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रशासनिक सचिवों से यह आग्रह किया गया कि प्रक्रियाधीन बजट आश्वासनों को कार्यान्वित करने के हर सम्भव प्रयास करें। यदि किसी बजट आश्वासन के कार्यान्वयन में कोई समस्या आ रही हो अथवा चालू वित्त वर्ष में कार्यान्वयन सम्भव नहीं हो पा रहा है तो सम्बन्धित मा० मन्त्री के माध्यम से मामला माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित किया जाए। यह भी निर्देश दिये कि समस्त विभागीय सचिव कार्यान्वित बजट आश्वासनों से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को अवगत करवाएँ और नवीनतम प्रगति योजना विभाग को उपलब्ध करवाएँ।

बैठक अध्यक्ष एवं समस्त उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

| सर्व श्री/ श्री मति/ कु० | | |
|--------------------------|----------------------|---|
| 1 | मनीषा नन्दा | अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण) एवं विचार्युक्त (राजस्व) |
| 2 | रामसुभग सिंह | अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन, वन) |
| 3 | निशा सिंह | अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मुद्रण एवं लेखन) |
| 4 | संजय गुप्ता | अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशुपालन, आयुर्वेद, सहकारिता) |
| 5 | मनोज कुमार | अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह, उद्योग, तकनीकी शिक्षा) |
| 6 | आर०डी० धीमान | अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य, उद्यान, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कार्मिक, प्रशिक्षण) |
| 7 | प्रबोध सक्सेना | प्रधान सचिव (विद्युत, शहरी विकास, गैर परम्परागत उर्जा स्रोत, नगर एवं ग्राम योजना) |
| 8 | जगदीश चन्द्र शर्मा | प्रधान सचिव (आबकारी कराधान, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी) |
| 9 | ओंकार चन्द शर्मा | प्रधान सचिव (जनजातीय विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि, शिक्षा) |
| 10 | दिवेश कुमार | सचिव (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य) |
| 11 | डॉ० आर० एन० बत्ता | सचिव (ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, परियोजना अनुश्रवण, सा०/ सचि० प्रशासन, सैनिक कल्याण) |
| 12 | दिनेश मल्होत्रा | सचिव (युवा सेवा एवं खेल) |
| 13 | अजय कुमार | प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन |
| 14 | डॉ० अमरजीत कु० शर्मा | निदेशक, उच्च शिक्षा |
| 15 | रोहित जमवाल | निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा |
| 16 | के० के० शर्मा | निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति |
| 17 | राजेश शर्मा | उप-सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) |
| 18 | बलबीर सिंह | उप-सचिव (प्रशासनिक सुधार) |
| योजना विभाग | | |
| 1 | अनिल कुमार खाची | अतिरिक्त मुख्य सचिव |
| 2 | डॉ० बसु सूद | सलाहकार |
| 3 | रविन्द्र कुमार | उप निदेशक |
| 4 | दिनेश कुमार | स०अनुसन्धान अधिकारी |